>

Title: Regarding misuse of MPLAD fund and delay in implementation of development work.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सांसद निधि की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो भी कारण हो या राज्य के जो संबंधित जिला अधिकारी या सीडीओ हैं और यहां के एमपी लैड्स का जो विभाग है, उनके बीच में आपस में समन्वय न होने के कारण बहुत से पिछले पैसे सांसदों के पड़े रहते हैं जिससे वे अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसमें समय फिक्स किया जाए कि इतने दिनों में वो पैसा चला जाए और खर्च भी हो जाए, उसके बाद दूसरी किश्त उनको जानी चाहिए। दूसरी मांग करना चाहूंगा कि जो वहां पर निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसकी क्वॉलिटी और क्वांटिटी का भी समय समय पर निरीक्षण केन्द्र सरकार द्वारा निगरानी समिति भेजकर वहां पर कराया जाना चाहिए और जो रिपोर्ट सीडीओ द्वारा यहां मंगायी जाती है, यहां से रिपोर्ट भेजी जाती है, उन दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित होना चाहिए तभी जाकर समय से एपी लैड्स का पैसा पहुंच सकता है।

मैं अपने क्षेत्र कौशाम्बी, उ.प्र. की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जहां पर करीब डेढ़ दो साल से करीब दो करोड़ -ढ़ाई करोड़ रुपये मैंने विद्युत विभाग को दिया है, आज भी उस पैसे का चैक भी जिलाधिकारी सीडीओ के माध्यम से कट गया है लेकिन तमाम छोटे छोटे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बिजली की जरुरत है, तार, खम्भे और ट्रंसफॉर्मर की जरुरत है, वहां के लिए चैक दिया गया है लेकिन आज तक वहां पर काम नहीं हो पाया है। इसलिए मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार इसकी जांच कराए। एक अन्य बात और मैं कहना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र के अलावा बाहर जो दस लाख रुपये हम देते हैं, वो भी अगर दूसरे जिले में हम देते हैं तो उसका काम भी समय से नहीं हो पा रहा है। अभी लेटेस्ट हम लोगों को सरकुलर मिला कि दस लाख रुपये अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो विकलांग है, उनको हम देते हैं लेकिन तुंत उसके बाद उस पर रोक लगा दी गई। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The hon. Member, you have to make only one point.

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं चाहता हूं कि वो दस लाख रुपये निर्वाचन क्षेत्र में भेजे जाएं ताकि सभी माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो विकलांग व्यक्ति हैं, उनको कृत्रिम अंग दे सकें और जो लिमिट रखी गई है कि एक साल में पचास लाख से ज्यादा रुपये स्कूलों में खर्च नहीं कर सकते, उसको खत्म किया जाए।

MR. CHAIRMAN: The hon. Member, you can raise this issue in the meeting of the MPLAD Committee.

श्री शैलेन्द्र कुमार : सर, वहां तो हम इस मुद्दे को उठाएंगे ही लेकिन सांसद निधि का मुद्दा है, इसिलए उसको हम रखना चाहते हैं। एक संस्था को 25 लाख रुपये जो देने की बात है, वह भी टाइम बाउंड उसको रखा जाए ताकि सांसद अपने क्षेत्र का विकास अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसको करे। धन्यवाद।